शिक्षा नीति का वर्तमान परिपेक्ष्य

*डॉ. भावना अभिषेक प्रधान
**डॉ. अंजलि पावले
***डॉ. एम.पी. रोहणी

प्रस्तावना :

86 वें संविधान संशोधन 2002 में 21 (क) शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसके तहत राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें 6– 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निः शुल्क शिक्षा मिल सके, यह प्रावधान ही शिक्षा के महत्व को बताता है शिक्षा नीति एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत करती है जो शिक्षा की रूपरेखा का पहले से और अधिक स्पष्ट करती है, और अधिक विस्तारित करती है, और अधिक इसके बहुआयामी रूप को बताती है। यह एक ऐसा रास्ता बनाने का सुन्दर प्रयास है जिसमें चलकर हमारा देश शिक्षा के उद्देश को प्राप्त कर सकता है, शिक्षा के स्तर को और बेहतर किया जा सकता है, शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने का यह कुशलतम प्रयास है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति :–

स्वतंत्र भारत में हमेशा से स्वतंत्र भारत में हमेशा से यह महसूस किया गया है कि शिक्षा ही विकास के केंद्र बिंदु में स्थित है शिक्षा ही देश के सर्वांगीण विकास का आधार है यह पहली बार नहीं हुआ है कि शिक्षा की राष्ट्रीय नीति बनाई गई है।

शिक्षा का इतिहास :–

प्राचीन काल में भी हमारे देश में शिक्षा के महत्व को समझ गया प्राचीन भारत का इतिहास मध्यकालीन भारत का इतिहास तथा समसामयिक इतिहास इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिक्षा का महत्व हमेशा से ही समझा एवं माना गया है जैसे –

प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशेषता :–

प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के तहत निम्न विशेषताएं शामिल हैं –

1. जीवन पर आधारित मूल्य पर शिक्षा दी जाती थी।
2. विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर बोल दिया जाता था।
3. विद्यार्थी को सामाजिक विकास के तहत शिक्षा दी जाती थी जिसके तहत विद्यार्थी सामाजिक जीवन उसके महत्व और इसकी आवश्यकता को भली भांति समझ सके।
4. व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी।

5. आश्रमों की व्यवस्था थी जहां गुरु शिष्य परंपराओं का पालन किया जाता था शिष्य अपने कर्तव्यों को भली भांति सीखना था अपने दायित्व से परिचित होता था ।

प्राचीन भारतीय शिक्षा के केन्द्र

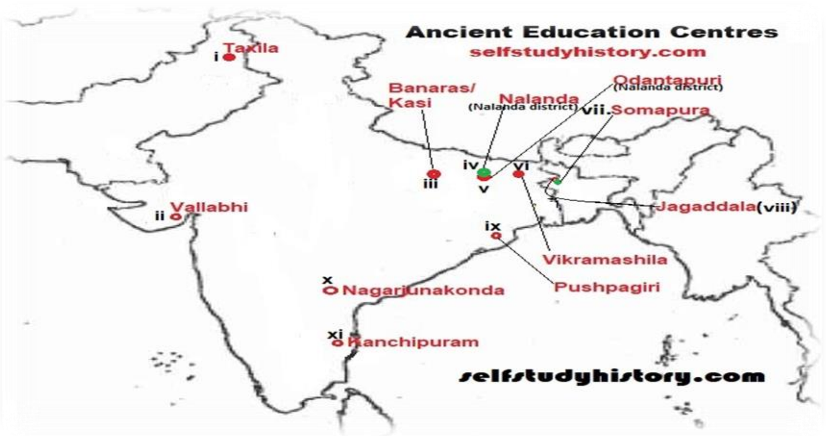

मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशेषताः–

इसी प्रकार मध्यकालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की की भी विशेषताएं इस प्रकार हैं जैसे

1. पहले यह भी जीवन मूल्य पर आधारित शिक्षा प्रणाली पर केंद्रित थी ।

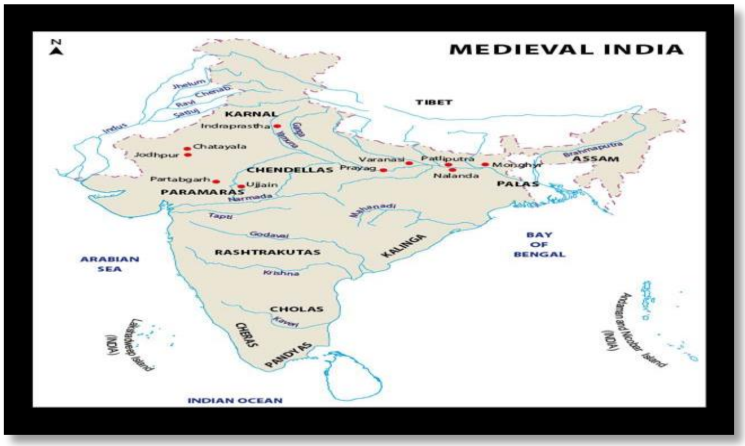

मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के केन्द्र

2. इस काल में भी इस काल में भी सैद्धांतिक शिक्षा के साथ–सा द प्रयोग शिक्षक प्रणाली को शामिल किया गया था जिससे विद्यार्थी सिद्धांतों के साथ–साथ प्रयोग के महत्व को समझ सके।
3. विद्यार्थियों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाती थी ।

आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली की विशेषताः–

इसी प्रकार वर्तमान या आधुनिक शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं इस प्रकार हैं

1. वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी प्राचीन शिक्षक प्रणाली को शामिल किया गया है साथ ही तकनीकी शिक्षा को महत्व स्थान मिला है।
2. दूसरी शिक्षण व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलने के लिए सरकार की भूमिका बढ़ी है सरकार के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई है।
3. तीसरा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु उचित वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

आधुनिक भारतीय शिक्षा के केन्द्र

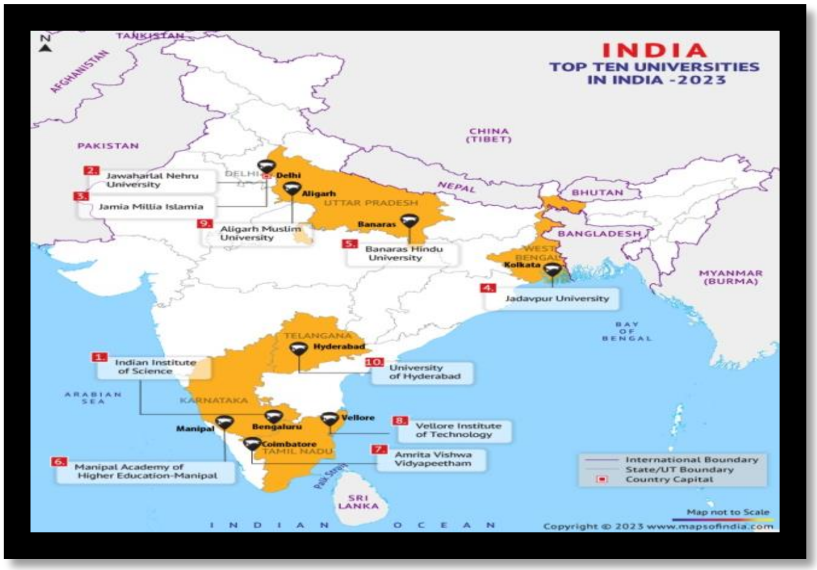

हम यह है कह सकते हैं कि विभिन्न कालों में शिक्षा की प्रणालियों में बदलाव किए गए हैं आवश्यक तत्वों को शामिल कर समय की मांग के अनुरूप इन प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव हुए हैं।

शिक्षा से लाभः–

हम यह बात भली–भांति जानते हैं की शिक्षा का मानव जीवन में बड़ा ही महत्व है शिक्षा आर्थिक

सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्व रखता है जिन्हें हम निम्न बिंदुओं से जानने का प्रयास करते हैं–

1 देश के आर्थिक विकास में वृद्धि

2 शिक्षा ग्रामीण विकास में सहायक

3 शिक्षा जनसंख्या को नियंत्रित करने में सहायक

4 मानव संसाधन का विकास

5 वर्तमान वभावी पीढ़ी के गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक

6 विज्ञान व अनुसंधान का आधार

7 व्यक्तित्व के विकास में सहायक

1 देश के आर्थिक विकास में वृद्धि–

शिक्षा व्यक्ति का बौद्धिक विकास करने में सहायक होती है, व्यक्ति में कौशल विकास को बढ़ावा मिलता है शिक्षा के विस्तार से एक और श्रम शक्ति में उत्पादकता बढ़ती है, साथी अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होता है जैसे आधारभूत संरचना का विकास होता है।विद्यालयों के निर्माण से मजदूरों को कार्य मिलता है शिक्षकों की भर्ती से रोजगार आदि का सृजन होता है बृहद रूप से देखा जाए तो सेवा व अनुसंधान क्षेत्र के विकास का आधार ही शिक्षा होती है।

2 शिक्षा ग्रामीण विकास में सहायक–

भारत में आज भी 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यो में लगी है, शिक्षा के विकास से ग्रामीण क्षेत्र का विकास होता है इन क्षेत्रों में लोग कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर लाभ कमा सकते हैं, कृषि में विस्तार हेतु आवश्यक जानकारी एकत्र कर सकते हैं जिससे लाभ कमा सकते हैं। घरेलू व कुटीर उद्योगों का विकास करके अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं।

3 शिक्षा पर जनसंख्या नियंत्रण–

देश में बहुत सारी नीतियां बनती इस करने में सक्षम है, किंतु जनसंख्या का आधिक्य इन योजनाओं को फलीभूत नहीं होने देता या सीधे शब्दों में बढ़ती हुई जनसंख्या देश के विकास में बाधक बनती है, शिक्षा से समाज में व्याप्त गलत धारणाएं टूटती हैं, महिला शिक्षा को बढ़ावा देने से समाज में सकारात्मक बदलाव आते हैं, लोगों की सोच बदलती है और वह छोटे परिवार अच्छा स्वास्थ्य आदि बातों को मानते हैं, अंधविश्वास का खंडन होता है लोग परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को अपनाते हैं साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों के महत्व को समझते हैं शिक्षा का जनसंख्या नियंत्रण में बहुत बड़ा योगदान होता है।

4 मानव संसाधन का विकास–

हम इस बात से परिचित हैं कि देश के विकास में प्राकृतिक संसाधन का जितना योगदान है उतना ही योगदान मानव संसाधन का है शिक्षा व्यक्ति की गुणवत्ता बढ़ती है जिन स्थानों पर शिक्षा का स्तर बेहतर है वह स्थान तीव्र गति से विकास कर रहे हैं देश के भीतर भी विभिन्न राज्यों में हम देख सकते हैं कि जिन राज्यों में

शिक्षा का स्तर बेहतर है शिक्षण संस्थान है बेहतर आधारभूत संरचना है वे राज्य अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर विकास कर रहे हैं

शिक्षा नीति का वर्तमान परिपेक्ष्यः—

"शिक्षा व अस्त्र है जिसके माध्यम से हम दुनिया में बदलाव ला सकते हैं।"

नेल्सन मंडेला

स्वतंत्रता की 20—21 वर्षों बाद ही 1986,24 जुलाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी जिसमें मुख्य रूप से कृषि तथा व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया था उसके पश्चात 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई यह नीति बहुत बदलाव हुआ उसे समय की परिस्थितियों की मांग के अनुरूप थी प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल के दौरान इस नीति को लाया गया जिसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को समाज के लिए और अधिक उपयोगी व पहुंच तक लाना था साथ ही शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना था। 1987 जनवरी में बनी 1986 सबके लिए शिक्षा नई शिक्षा नीति, सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने की बात कही गई की विशेषताओं इस प्रकार हैं :—

नई शिक्षा नीति का विकास क्रम :—

नई शिक्षा नीति 2020 की जानने से पहले हम इसके क्रमिक विकास को देख सकते हैं।

- 1952 माध्यमिक शिक्षा आयोग — अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदलियार
- 1964 शिक्षा आयोग कोठारी आयोग अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी
- 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति
- 1993 परिवर्तन हुए
- 2020 नई शिक्षा नीति — अध्यक्ष अंतरिक्ष वैज्ञानिक की कस्तूरीरंगन, 29 जुलाई 2020 को घोषित

1986 की शिक्षा नीति की विशेषताएंः—

1. 1947 की स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा को पहली बार इतना महत्व दिया गया ।
2. पूरे राष्ट्र में पाठ्यक्रम का रूप एक ही रहे इस पर विशेष ध्यान दिया गया ।
3. शिक्षा को लोगों की पहुंच तक लाने का प्रयास किया गया ।
4. नवीन विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया, उदाहरण के तौर पर नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई।
5. 10+2+3 शिक्षा संरचना लाई गई जिसे सभी राज्यों ने स्वीकार किया।
6. ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड चलाई गई।
7. व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया ।

8. मुक्त विद्यालयों की स्थापना की गई ।
9. त्रीभाषा सूत्र का प्रावधान किया गया ।
10. पहले से स्थापित संस्थाओं को मजबूत बनाने का प्रावधान किया गया।

देश की शिक्षा नीतिः–

नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने के बाद लागू किया गया है इसके तहत स्कूलों व कॉलेज की शिक्षा नीति में बदलाव लाए गए हैं।

उद्देशः–

- छात्र छात्राओं पढ़ाई के साथ–साथ किसी लाइफ स्किल से सीधा जोड़ना।
- सहायक पाठ्यक्रम को मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाना।
- तकनीकी शिक्षा को महत्व देना।
- सभी को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने को महत्व देना।
- 2030 तक हर बच्चे के लिये शिक्षा।
- शोध कार्य को बढ़ावा देना।
- बहु भाषा को बढ़ावा देना।
- बच्चों की सोच को विकसित करना।
- विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना।
- शिक्षा में गुणवत्ता हेतु लचीलापन लाना।
- शिक्षा की नीति को पारदर्शी बनाना।

परिवर्तनः–

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया।
- शिक्षा कार्यक्रम शिक्षकों की प्रशिक्षण पर जोड़ दिया गया।
- स्कूल टीचर्स एडल्ट एजुकेशन को जोड़ा जाएगा।
- प्राचीन ज्ञान पद्धतियों को समग्रता के साथ शिक्षा से जोड़ने का काम करेगा।
- प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में बहु भाषा बहुभाषिकता को प्राथमिकता के साथ शामिल करना।

- 5+3+3+4 के नया फार्मूला लागू किया गया।
- उच्च शिक्षा में 1 वर्ष में सर्टिफिकेट, 2 वर्ष डिप्लोमा, 3 वर्ष डिग्री।
- 12 वर्ष की स्कूल शिक्षा वी 3 वर्ष की मुक्त शिक्षा होगी।
- पांचवी तक मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन अध्यापन कार्य किया जाएगा।
- छठवीं से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत होगी।
- डिजिटल अध्यापन को बढ़ावा दिया जाएगा।

सुझाव :–

1 अन्य देश के बजट की तुलना में भारत में शिक्षा पर वह काम है जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है।

2 सरकारी नीतियों के कुशल क्रियान्वयन की आवश्यकता है ।

3 आधारभूत संरचना का विकास इस प्रकार हो की अति कठिन दुर्गम क्षेत्रों तक बेहतर शिक्षा को पहुंचाया जा सके

4 कोरोना महामारी के कारण प्रभावित विद्यार्थियों के विकास के लिए ठोस ध्यान देने की आवश्यकता है।

5 नई शिक्षा नीति के तहत आए पाठ्यक्रमों में परिवर्तन के अनुरूप अध्ययन सामग्री की व्यवस्था पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

6 शिक्षक के प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ–साथ प्रशिक्षण में गुणवत्ता बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए।

7 शिक्षण विभागों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती किया जाए जिससे शिक्षण सत्र शिक्षक के अभाव कार्य में ना करना पड़े।

8 समय की मांग के अनुरूप समय समय पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए।

9 शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था पर जोर देने की आवश्यकता है।

10 शिक्षण संस्थानों को गुणवत्ता पूर्ण बनाने की आवश्यकता है अध्ययन कार्य व प्रयोगात्मक कार्य से विद्यार्थियों का परिचित कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

निष्कर्षः–

'शिक्षा पर किया गया व्यय बोझ न होकर बुद्धिमत्ता पूर्वक किया गया निवेश समझ जाना चाहिए'

T.W. शूल्ज

भारत जैसे वृहद राष्ट्र में शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार लाना चुनौती भरा कार्य है नई शिक्षा नीति सरकार का बहुत सराहनीय प्रयास है जिसके माध्यम से शिक्षा को सभी तक पहुंचा जा सकता है इसके लिए आवश्यक है की शिक्षण

कार्य सरकार की भूमिका सरकार के विभिन्न अंग विद्यार्थी, अभिभावक सभी अभी सभी अपने–अपने कर्तव्यों का अपनी जिम्मेदारियां का कुशलता पूर्वक निर्वहन करें शिक्षा नीति सभी के लिए है जिसे मूर्त रूप में लाने के लिए सभी को प्रयास करने की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं निःसंदेह देश में शिक्षा का स्तर पहले से बेहतर होगा।

***सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र**
****सहायक प्राध्यापक हिन्दी**
*****सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान**
डॉ. भेवर सिंह पोर्ते शा. महा. पेण्ड्रा
जिला जीपीएम (छ.ग.)

संदर्भसूचीः–

1. Alliance for Excellent Education (2012). The Digital Learning Imperative: How Technology and Teaching Meet Today's Education Challenges, 10.
2. Aud, S., Hussar, W., Johnson, F., Kena, G., Roth, E., Manning, E., Wang, X., & Zhang, J. (2012). The Condition of Education 2012 (NCES 2012-045). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. Washington, D.C. Retrieved from http://nces.ed.gov/pubsearch.
3. Cavanaugh, C. (2013). Student achievement in elementary and high school. In M. G. Moore (Ed.), Handbook of distance education (3rd. ed.) (170–184). New York: Routledge.
4. Horn, M., & Staker, H. 5 Skills for Blended-Learning Teachers. THE Journal. October 4, (2012). Retrieved from http://thejournal. com/articles/2012/10/04/5-skills-for-blended-learning-teachers.aspx.
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
6. https://www.edgenuity.com/wp-content/uploads/2017/01/Role-of-the-Teacher.pdf
7. https://www.google.com/search?q=blended+learning+environment&oq=Blended+Learning+Environment&aqs=chrome.0.0i512l3j0i22i30j0i15i22i30j0i22i30l5.5391j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
8. https://www.learnupon.com/blog/what-is-blended-learning/
9. Strauss, Valerie (September 22, 2012). "Three fears about blended learning". *The Washington Post*.
10. https://www.mapsofindia.com/education/top-ten-universities-in-india.html
11. https://aiemd.org/medieval-india-ppt-pdf/